



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, जून 28, 1990/असाढ़ 7, 1912
No. 361] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1990/ASADHA 7, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1990

का. आ. 518 (अ):—गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पणजी, जो एक बहु-
राज्य सहकारी सोसायटी है और जिसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के
अधोक्त रजिस्ट्रिकृत माना गया है, गोवा राज्य और दमण और द्वोय संघराज्य क्षेत्र के लिए

एक विशेष सहकारी बैंक है जो जो भूमि और वास्तु को भी संबंधों के लिए सहकारी सोसाइटियों के लिए आर्थिक, आर्थिक और वित्तीय उधारों का विश्वव्यापी करता है और दिए गए वित्तीय उधार पूर्वक बैंक की उप-विधियों के अनुसार 10 से 15 वर्षों की अवधि के लिए होते हैं ;

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा छिद्रियों, आवेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 के नियम 10 का उपनियम (3) यह अनुबंधित करता है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए उधार के प्रतिस्पर्धियों को अवधि यह होगी जो उप-विधियों में उपबंधित की जाए किन्तु किसी भी दशा में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

10 से 15 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घ कालिक उधारों द्वारा वित्तपोषण पूर्वक नियमों के नियम 10 के उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार नहीं है इसलिए गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने दीर्घकालिक उधारों का अविच्छिन्न वित्तपोषण शुरू करने के लिए नियम 10 के उक्त उपनियम (3) से छूट मांगी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 99 की उपधारा (2) (क) (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पणजी को, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार सम्पत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा छिद्रियों, आवेशों और विनिश्चयों का निष्पादन (नियम, 1985 के नियम 10 के उपनियम (3) के उपबंधों से छूट देती है ।

[सं. एल-11012/3/90-एल एंड एम]

संगीता मेरोला, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1990

S.O. 518(E).—Whereas the Goa State Cooperative Bank Limited, Panaji, a multi-State co-operative society deemed to be registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984, is an apex co-operative bank for the State of Goa and the Union Territory of Daman and Diu and is financing short-term, medium-term and long-term loans for co-operative societies both for agricultural and housing sectors and the long-term loans advanced range for a period of 10 to 15 years, as per bye-laws of the aforesaid Bank;

Whereas sub-rule (3) of rule 10 of the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, orders and Decisions) Rules, 1985 stipulation that the period of repayment of the loan is ued by a multi-State co-operative society shall be as may be provided in the bye-laws, but in no case exceeding five years;

Whereas the financing of long-term loans ranging for a period of 10 to 15 years, being not in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 10 of the aforesaid Rule, the Goa State Co-operative Bank Limited has sought exemption from the said sub-rule (3) of rule 10 to facilitate uninterrupted financing of long-term loans:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) (a)-(i) of section 99 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) the Central Government hereby exempts the Goa State Co-operative Bank Limited, Panaji, from the provisions of sub-rule (3) of rule 10 of the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985.

[No. L-1/1012/3/90-L&M]

SANGITA GAIROLA, Dy. Secy.

